संपादकीय जागरण

मंगलवार, 26 जून, 2018 : द्वि. ज्येष्ठ शुक्ल 13 वि. 2075

दूसरे की निंदा से अपने ही व्यक्तित्व का क्षरण होता है

मानसून सत्र के आसार

संसद के मानसून सत्र की तिथि घोषित होते ही पिछले बजट सत्र की याद आ जाना स्वाभाविक है। बजट सत्र ने नाकामी का इतिहास रचने के साथ ही संसदीय परंपरा को श्रीहीन करने का भी काम किया था। जहां वित्त विधेयक बिना बहस के पारित हुआ था वहीं दोनों सदनों में कोई खास विधायी कामकाज भी नहीं हो पाया था। बजट सत्र के दूसरे चरण में तो दोनों सदनों में करीब-करीब हर दिन नारेबाजी होती थी और कई बार यह पता ही नहीं चलता था कि नारेबाजी करने वाले दलों के सांसद चाहते क्या हैं? इस सत्र के आखिरी दिनों में यह भी दिखा था कि विपक्ष की तरह सत्तापक्ष भी संसद चलाने के लिए इच्छुक नहीं, क्योंकि विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव पर जोर दे रहे थे। चूंकि दोनों पक्ष एक-दूसरे को संसद न चलने का दोषी बताते रहे इसलिए आम जनता के लिए समझना कठिन हो गया कि आखिर संसद किस कारण ठहरी है? कहना कठिन है कि 18 कार्य दिवसों वाले मानसून सत्र में क्या होगा, लेकिन आसार अच्छे नहीं दिख रहे हैं। कर्नाटक में सरकार बना लेने और उपचुनावों में भाजपा से बेहतर प्रदर्शन करने के चलते विपक्ष कहीं अधिक उत्साहित तो है ही, वह आगामी आम चुनाव में भाजपा के खिलाफ महागठबंधन बनने की संभावनाएं भी देख रहा है। निराशाजनक यह है कि वह पहले से कहीं अधिक नकारात्मकता से भी भरा हुआ नजर आ रहा है। हैरत नहीं कि वह बजट सत्र की तरह मानसून सत्र को भी बाधित करने की कोशिश करे।

अगर विपक्षी दल संसद में कोई कामकाज न होने देने पर अड़ जाते हैं तो फिर वही हो सकता है जो बीते सत्र में हुआ था। सत्तापक्ष को विपक्ष के असहयोग भाव से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसे ऐसी कोई रणनीति बनानी होगी जिससे जरूरी विधायी कामकाज पूरे हो सकें। निःसंदेह मोदी सरकार के कार्यकाल के चार वर्ष पूरे होने के साथ ही राजनीति चुनावी माहौल में प्रवेश कर गई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि संसद में कोई काम ही न होने दिया जाए। संसद को बाधित करने का मतलब है देश को आगे बढ़ने से जानबूझकर रोकना। क्या इससे बड़ी विडंबना और कोई हो सकती है कि हमारे राजनीतिक दल ही देशहित को हाशिये पर रखें। बेहतर हो कि सभी दल इस भाव का वास्तव में परिचय दें कि दल से बड़ा देश है। उन्हें अपनी छवि और जनहित के साथ ही संसद की मर्यादा की भी चिंता करनी चाहिए। न चलने वाली संसद अपनी गरिमा की रक्षा नहीं कर सकती। यदि मानसून सत्र में प्रस्तावित विधेयकों पर अपनी अलग राय अथवा असहमति के नाम पर विपक्ष उन्हें पेश होने की ही नौबत नहीं आने देता तो यह लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ काम होगा। इसका कोई औचित्य नहीं कि दलगत राजनीतिक मतभेदों या फिर चुनावी समीकरण दुरुस्त करने के नाम पर संसद राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मसलों पर विचार-विमर्श करने और कानून बनाने का अपना मूल काम ही न कर सके। यह वक्त की मांग और जरूरत है कि सत्तापक्ष और विपक्ष मानसून में मिलकर काम करने के किसी एजेंडे पर सहमत हों।

सामाजिक न्याय की उम्मीद

पिछड़ी जातियों के आरक्षण कोटे में अति पिछड़ी जातियों का आरक्षण तय करने की दिशा में प्रदेश सरकार तेजी से काम कर रही है। अति पिछड़ों की कई जातियां आरक्षण का लाभ पाने से वंचित रही हैं। दरअसल, पिछड़ी जातियों को आरक्षण का प्रावधान इसी उद्देश्य से किया गया था कि उन्हें भी धीरे-धीरे 'लेवल प्लेईंग फील्ड' हासिल हो सकेगा। उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उन्नयन के लिए देश में 27 फीसद आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन पिछड़ों में भी इसका अधिक लाभ सक्षम जातियां ही उठा रही हैं। आंकड़े बताते हैं कि इसमें भी यादव और कुर्मी बिरादरी ही ज्यादा लाभ ले पा रही है। यादवों की आबादी नौ फीसद है, लेकिन उन्हें नौकरियों में 132 फीसद तक हिस्सेदारी हासिल हुई। कुर्मी जाति की आबादी पांच फीसद है, लेकिन उन्हें नौकरियों में 242 फीसद तक हिस्सेदारी वे पा चुके हैं। जबकि दूसरी ओर 63 ऐसी जातियां हैं जो पिछड़ा वर्ग में 14 फीसद हैं, लेकिन उन्हें नौकरियों में हिस्सेदारी महज 77 फीसद हासिल हुई। ऐसे में अब पिछड़ों के आरक्षण में से भी अति पिछड़ों के लिए अलग आरक्षण की व्यवस्था की जरूरत आ पड़ी है।

अब पिछड़ों के आरक्षण में से भी अति पिछड़ों के लिए अलग आरक्षण की व्यवस्था की जरूरत आ पड़ी है

हालांकि यह समस्या पुरानी है और अति पिछड़ों को आरक्षण कोटे में भी अलग से आरक्षण देने के प्रयास पहले भी हो चुके हैं, लेकिन उस प्रयास में कुछ कमियों के चलते अदालत ने उसे मानने से इन्कार कर दिया था। जाहिर-सी बात है यह आनन-फानन में या सतही रूप से व्यवस्था करने का मसला नहीं है। योगी सरकार अति पिछड़ों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थितियों का आकलन करवा रही है, ताकि अति पिछड़ों के साथ न्याय किया जा सके। सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय और सामाजिक उन्नयन की दिशा में सरकार के इस कदम से अति पिछड़ों में भी नई उम्मीद जागी है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने के लिए भारत को उसके साथ कूटनीतिक रिश्तों में कटौती करनी चाहिए?

आज का सवाल
क्या भारतीय क्रिकेट टीम में चयन के लिए यो-यो फिटनेस टेस्ट की अनिवार्यता सही है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

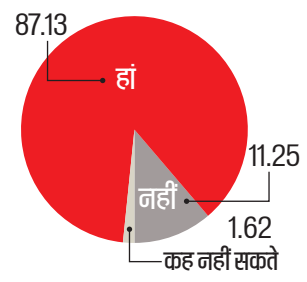

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

कश्मीर समस्या के हल की राह

बलबीर पुंज

यदि घाटी में मसला 'मानवाधिकार' और 'लोकतांत्रिक व्यवस्था' का है तो आइएस का झंडा लहराकर 'निजाम-ए-मुस्तफा' की मांग क्यों की जा रही है?

पिछले डेढ़ महीनों के दौरान जम्मू-कश्मीर में जिस प्रकार का राजनीतिक एवं सामाजिक घटनाक्रम देखने को मिला उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उभरे हैं। पहला-राजनीतिक अधिष्ठानों ने 2014 से पहले कश्मीर समस्या के हल हेतु जिन हिमालयी गलतियों का अनुसरण किया उसे फिर दोहराने का प्रयास हुआ। दूसरा-घाटी में असंतोष का कारण क्षेत्रीय असमानता, गरीबी, बेरोजगारी नहीं है। तीसरा-कश्मीर का एक वर्ग शहीद भारतीय सैनिक औरंगजेब के बजाय बुरहान वानी जैसे आतंकियों को अपना आदर्श मानता है। और चौथा- यहां संघर्ष केवल कट्टर इस्लामी मानसिकता, उसके मूर्त रूप आतंकियों-जिहादियों और उनके मानवाधिकारों के रक्षकों से है। कश्मीर संकट के विरुद्ध उपयुक्त नीतियां अपनाने पर देश का एक वर्ग सदैव सवाल उठाता रहा है और इसी का परिणाम है कि पिछले सात दशकों में यह समस्या अब भयावह रूप ले चुकी है। जब रमजान में केंद्र सरकार ने सशर्त सैन्य संघर्ष विराम की घोषणा की तो उसके परिणाम ने क्रूर वास्तविकता को रेखांकित करते हुए स्थापित कर दिया कि ऐसी नीतियों से बदलाव संभव नहीं है। रमजान से एक माह पहले घाटी में 20 आतंकी घटनाएं हुईं तो रमजान में 73। पहले 14 आतंकी मारे गए तो रमजान में 22। पहले 5 जवान शहीद हुए तो रमजान में 9। इस दौरान सुरक्षा बलों पर 107 बार पथराव हुआ तो पत्रकार शुजात बुखारी की निर्मम हत्या कर दी गई?

लगभग तीन दशक पहले जब पंजाब में आतंकवाद चरम पर था तब भी देश के कुछ बुद्धिजीवी कहा करते थे कि यदि चंडीगढ़ पंजाब को सौंप दिया जाए या उसे अधिक स्वायत्तता दे दी जाए, बेरोजगारों को नौकरी दे दी जाए तो वहां शांति बहाल हो जाएगी। बहरहाल पंजाब के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक केपीएस गिल की कार्रवाइयों से कट्टरपंथियों की रीढ़ टूट गई और पंजाब की एक समस्या समाप्त हो गई। जम्मू-कश्मीर में पीडीपी के साथ बीते तीन वर्षों से चल रही बेमेल गठबंधन सरकार से जब भाजपा ने समर्थन वापस लिया तब विरोधी दलों ने कश्मीर संकट के लिए एक स्वर में मोदी सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, 'भाजपा-पीडीपी गठबंधन ने जम्मू-कश्मीर को आग में झोंक दिया, जिसमें निर्दोष लोग और हमारे बहादुर जवानों की जान चली गई। भारत को सामरिक रूप से नुकसान हुआ।' क्या मई 2014 से पहले कश्मीर शांत था? कश्मीर में ऐतिहासिक भूलों को घाटी में आए दिन होने वाले आतंकी हमलों और पथराव से अलग करके नहीं देखा जा सकता। क्या यह सत्य नहीं कि घाटी की वर्तमान स्थिति की नींव पंडित नेहरू की शेख अब्दुल्ला से मित्रता और दोनों की जम्मू-कश्मीर के अंतिम महाराजा हरिसिंह से बैरभाव ने नहीं रखी थी? क्या जेहादी तत्वों और अलगाववादियों से कांग्रेस की समझौता करने की प्रवृत्ति ने कश्मीर संकट को और नहीं बढ़ाया? क्या इसकी अनदेखी की जा सकती है कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने कांग्रेसी नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के उस वक्तव्य का समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा था, 'सैन्य ऑपरेशन में आतंकियों से अधिक आम नागरिक मारे जाते हैं?' क्या यह घटनाक्रम कांग्रेस की विभाजनकारी मानसिकता का परिचायक नहीं?

अवधेश राजपूत

गुलाम नबी आजाद जिन 'आम नागरिकों' की बात कर रहे हैं उनमें से अधिकांश वे लोग होते हैं जो मुठभेड़ के समय आतंकियों का बचाव कर सुरक्षाबलों पर पथराव करते हैं। कांग्रेसी नेता सैफुद्दीन सोज कश्मीर की 'आजादी' का समर्थन कर रहे हैं। वास्तव में, कथित 'आजादी' और 'असंतोष' की जड़ें 'काफिर-कुफ्र' की अवधारणा में निहित हैं। इस मानसिकता ने विकराल रूप तब धारण किया जब भारतीय उपमहाद्वीप में 19वीं शताब्दी के अंत में सैयद अहमद ने 'द्विराष्ट्र' सिद्धांत का वैचारिक सूत्रपात किया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने मुस्लिम लीग और वामपंथियों की सहायता से पाकिस्तान के जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब 1931 में इसी शैक्षणिक अधिष्ठान से शिक्षित होकर शेख अब्दुल्ला कश्मीर लौटे तब उन्होंने रियासत के तत्कालीन महाराजा हरिसिंह के कथित सामंतवाद के खिलाफ मोर्चा खोलकर सांप्रदायिकता का बीजारोपण कर दिया, जिसका विषाक्त फल कालांतर में कश्मीरी पंडित विहीन घाटी और उग्र भारत विरोध के रूप में मिला।

जब तक पंडित नेहरू को अपने मित्र शेख अब्दुल्ला की असलियत का पता चला, तब तक वह कश्मीर संकट की नींव तैयार कर चुके थे। बढ़ती सेना को बिना पूरे कश्मीर को मुक्त कराए युद्धविराम की घोषणा, शेख अब्दुल्ला को सत्ता सौंपना, महाराजा हरि सिंह को निष्कासित करना, धारा 370 को पारित करना, मामले को संयुक्त राष्ट्र ले जाना और जनमत संग्रह की स्वीकृति देने जैसे फैसलों के कारण ही आज कश्मीर की यह दुर्गति हुई है। पाकिस्तान द्वारा 'जिहादियों' की घुसपैठ से कश्मीर का संकट और अधिक गहरा गया। अतीत के युद्ध परिणामों से पाकिस्तान समझ गया कि वह सीधे युद्ध के द्वारा कश्मीर पर कब्जा नहीं कर सकता। इसलिए उसने भारत की प्रारंभिक 'राजनीतिक गलतियों' का लाभ उठाकर जिहाद को सुलगाना शुरू कर दिया ताकि घाटी में मजहबी उन्माद और कट्टरवाद को जीवित रखा जा सके। हाल में फिर स्पष्ट हुआ कि पाकिस्तान कैसे अलगाववादियों के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर को मुद्दा बनाने की जुगत में है। 14 जून को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने कश्मीर में कथित मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी एक पक्षपाती रिपोर्ट जारी की जिसे छह अन्य देशों ने खारिज भी कर दिया। दिलचस्प यह है कि रिपोर्ट में लश्कर-ए-तैयबा और हिज्बुल मुजाहिदीन के लिए 35 से अधिक बार 'आर्म्ड ग्रुप' यानी 'हथियारों से लैस संगठन' शब्द का प्रयोग किया गया है जबकि संयुक्त राष्ट्र दोनों को आतंकी संगठन मानता है। यही नहीं, परिषद के मुखिया जैद राद-अल-हुसैन ने आइएसआइ के एजेंटों और हुर्रियत कांफ्रेंस नेताओं से भेंट भी की थी।

यदि हम कश्मीर समस्या का निदान चाहते है तो हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ढूंढने होंगे। पहला- घाटी में 98 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है और यदि इसी अनुपात में हिंदू-सिख-बौद्ध होते तो क्या तब भी संकट होता? यदि इसका उत्तर नहीं है तो फिर यह अंतर क्यों? दूसरा- यदि 1930-40 के दशक में शेख अब्दुल्ला का विरोध सामंतवाद, शोषण और भेदभाव के खिलाफ था तो महाराजा हरि सिंह के घाटी छोड़ने के 70 वर्ष बाद भी वहां खूनी संघर्ष क्यों जारी है? तीसरा- यदि घाटी में मसला 'मानवाधिकार' और 'लोकतांत्रिक व्यवस्था' का है तो पाकिस्तान-आइएस का झंडा लहराकर 'निजाम-ए-मुस्तफा' की मांग क्यों की जा रही है? चौथा- जब भारत सरकार केंद्रीय अनुदान का बड़ा हिस्सा जम्मू-कश्मीर को दे रही है तो घाटी की मस्जिदों से भारत की मौत की दुआ क्यों मांगी जा रही है? और पांचवां- आखिर क्यों शहीद सैनिक औरंगजेब की शवयात्रा में उतनी भीड़ नहीं जुटी जितनी अक्सर घाटी में आतंकियों के जनाजे में जुटती है? इन प्रश्नों के ईमानदारी से दिए उत्तरों में ही कश्मीर संकट के हल की संभावनाएं निहित हैं।

(लेखक राज्यसभा के पूर्व सदस्य एवं स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

आय दोगुनी करने का कठिन लक्ष्य

रमेश दुबे

मोदी सरकार के लिए इससे परिचित होना आवश्यक था कि एमएसपी में वृद्धि और कर्जमाफी से खेती का संकट दूर नहीं होगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2022 तक यानी अगले चार सालों में किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य को अपनी प्राथमिकता बनाए हुए हैं। हाल में उन्होंने किसानों से बात करते हुए फिर कहा कि उनकी सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे इस लक्ष्य के प्रति मोदी सरकार की गंभीरता का ही पता चलता है, लेकिन कई ढांचागत उपायों के बावजूद सरकार अब तक इस लक्ष्य की ओर बढ़ती प्रतीत नहीं हो रही है। जाहिर है कि इसीलिए सरकार की आलोचना की जाने लगी है। चूंकि मोदी सरकार मनरेगा जैसे लोक-लुभावन कार्यक्रम के बजाय दूरगामी उपायों के द्वारा किसानों की आमदनी बढ़ाने की कोशिश कर रही है इसलिए नतीजे आने में देर हो रही है। देश के विभिन्न हिस्सों के किसानों से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने मिट्टी, सिंचाई, बीज, उर्वरक, फसल बीमा, इलेक्ट्रॉनिक मंडी जैसे ढांचागत सुधारों की चर्चा करते हुए यह भी कहा कि सरकार ने कृषि संबंधी बजट की राशि को दोगुना कर दिया है। निःसंदेह बजट में कृषि क्षेत्र के लिए राशि बढ़ाई गई है, लेकिन समस्या यह है कि इन बहुआयामी उपायों के बावजूद न तो किसानों की आत्महत्या थम रही है और न किसान आंदोलन। ग्रामीण भारत की बदहाली कई कारणों का परिणाम है। प्रमुख कृषि उत्पादों की कीमतों में तेज गिरावट, गेहूं और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में मामूली बढ़ोतरी, कुदरती आपदाओं के कारण फसलों को भारी नुकसान से किसानों की बदहाली बढ़ी है।

हालांकि अनाज, दाल, मांस, दूध और प्रोटीन सहित सभी कृषि उपजों का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है, लेकिन किसानों को उनकी उपज की वाजिब कीमत नहीं मिल पा रही है। नोटबंदी और जीएसटी के चलते मांग में जो कमी आई है उसका खामियाजा भी खेती को भुगतना पड़ रहा है। खेती-किसानी की बदहाली का एक पहलू उदारीकरण के दौर में खेती की उपेक्षा से भी जुड़ा है। इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि कृषि प्रधान देश में खेती-किसानी की नीतियां आग लगे तो कुआं खोदो वाली रही हैं। उत्पादन से लेकर भंडारण-विपणन तक में कामचलाऊ नीतियों का नतीजा यह हुआ कि खेती घाटे का सौदा बन गई। एक कारण यह भी रहा कि राजनीतिक कारणों से सरकारें जितनी चिंता महंगाई की करती हैं उसका दसवां हिस्सा भी खेती-किसानी की नहीं करतीं। किसानों की समस्याएं इसलिए भी बढ़ती चली गईं, क्योंकि अब तक सरकारी नीतियों का लक्ष्य उत्पादन में बढ़ोतरी तक अधिक केंद्रित रहा है। उत्पादन में वृद्धि से यह मान लिया जाता था कि किसानों का समग्र विकास हो रहा है, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। विडंबना यह भी है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य भी सभी फसलों और सभी क्षेत्रों को नहीं समेट पाया है। जिस हरित क्रांति पर हम इतराते रहे हैं उसका दायरा चुनिंदा फसलों और इलाकों तक सिमटा रहा। दलहनी, तिलहनी फसलें और मोटे अनाज हरित क्रांति की परिधि से दूर ही रहे।

चूंकि हरित क्रांति में समय के साथ बदलाव नहीं किए गए इसलिए इस क्रांति के अगुआ रहे क्षेत्र भी बदहाली की ओर बढ़ते चले गए। कांग्रेसी शासन काल में एक बड़ी गलती यह भी हुई कि खेती की बदहाली को दूर करने के लिए ढांचागत सुधार करने के बजाय दान-दक्षिणा वाली योजनाएं शुरू की गईं ताकि किसानों का असंतोष उसे सत्ता से बेदखल न कर दे। काम के बदले अनाज योजना, मनरेगा, कर्जमाफी आदि इसी आत्मघाती नीति के कुछेक उदाहरण हैं। खेती-किसानी को जिस प्रकार वोट बैंक की राजनीति से जोड़ दिया गया उससे भी उसका विकास बाधित हुआ। समस्या यह है कि अब कोई भी सरकार इन कामचलाऊ योजनाओं में कटौती का जोखिम नहीं उठा पाती है। इससे खेती में दीर्घकालिक निवेश प्रभावित होता है। लंबे अर्से तक उपेक्षा के बाद मोदी सरकार ने खेती-किसानी के समग्र विकास के कदम उठाए हैं। इसके तहत मिट्टी से लेकर उपज के भंडारण-विपणन तक के उपाय किए जा रहे हैं ताकि खेती मुनाफे का सौदा बने। अब तक 13 करोड़ से ज्यादा मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांटे जा चुके हैं। इससे उर्वरकों के असंतुलित इस्तेमाल में कमी आई है। नीम कोटेड यूरिया के इस्तेमाल से उसकी कालाबाजारी रोकने में कामयाबी मिली है। सरकार किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज की भी आपूर्ति कर रही है। इसके अलावा कुछ अन्य उपाय भी किए गए हैं। क्या इसे दुर्भाग्य नहीं कहेंगे कि आजादी के 70 साल बाद भी देश की 60 फीसद कृषि भूमि मानसून की कृपा पर निर्भर है। मोदी सरकार ने हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की है और उसकी ओर से लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने को सर्वोच्च प्राथमिकता भी दी जा रही है। लगभग सौ परियोजनाएं जल्द ही पूरी होने वाली है।

किसानों की सबसे बड़ी समस्या है उपज की वाजिब कीमत न मिलना। इस समस्या को दूर करने के लिए मोदी सरकार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई-नाम शुरू किया है। अब तक 14 राज्यों की 585 मंडियां इससे जुड़ चुकी हैं, शेष 415 मंडियों को 2020 तक ई-नाम से जोड़ दिया जाएगा। किसानों को अपनी उपज की बिक्री के लिए अधिक दूर न जाना पड़े, इसके लिए देश की 22,000 ग्राम मंडियों का विकास करने की योजना है। ग्रामीण एवं कस्बाई इलाकों में इंटरनेट संबंधी नेटवर्क के मजबूत बनते ही इसका लाभ समूचे देश को मिलने लगेगा। जैविक उत्पादों की वैश्विक मांग का दोहन करने के लिए सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। मोदी सरकार के लिए इस हकीकत से परिचित होना आवश्यक था कि एमएसपी में बढ़ोतरी और कर्जमाफी से खेती का संकट दूर नहीं होगा।

शायद इस हकीकत को जानने के बाद ही सरकार खेती-किसानी को विविधीकृत कर रही है ताकि मौसमी उतार-चढ़ाव और खेती की बढ़ती लागत को किसान आसानी से झेल सकें। इसके तहत कृषि के साथ-साथ मत्स्य पालन, डेयरी, मधुमक्खीपालन जैसी आयपरक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा आलू, प्याज, टमाटर जैसे शीघ्र खराब होने वाली उपज की ढुलाई, संरक्षण एवं बिक्री को बढ़ावा देने के लिए जुलाई में 'आपरेशन ग्रीन' लांच किया जाना है। इस सबको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि मोदी सरकार खेती-किसानी को मुनाफे का सौदा बनाने के लिए ढांचागत सुधारों पर बल दे रही है इसीलिए वांछित नतीजे आने में देर हो रही है। एक बार आधुनिक कृषिगत आधारभूत ढांचा बन जाने के बाद खेती-किसानी की बदहाली दूर हो जाएगी, लेकिन यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि कृषि संबंधी आधारभूत ढांचे का निर्माण अपेक्षा के अनुरूप हो।

(लेखक केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी एवं कृषि मामलों के जानकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

विचार

दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं, जिसके मन में किसी भी प्रकार के विचार उत्पन्न न होते हों। उत्पन्न विचार महज दो ही प्रकार के हो सकते हैं, या तो सकारात्मक या फिर नकारात्मक विचार। मनुष्य के जीवन में विचारों का बहुत ही महत्व है। मानव अपने विचारों के द्वारा निर्मित प्राणी है। वैज्ञानिकों ने भी यह दावा किया है कि व्यक्ति जैसा सोचता है, वैसा ही बनता चला जाता है। उसके हाव-भाव और व्यवहार भी उसके विचार सरीखे हो जाते हैं। हमारे जीवन में वक्त व परिस्थितियां कभी भी एक समान नहीं रहतीं। वे कभी अनुकूल तो कभी हमारे प्रतिकूल होती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में सभी मनुष्यों के विचार सकारात्मक ही होते हैं, लेकिन वह चीज जो किसी एक इंसान को दूसरों से अलग बनाती है, वह है, विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मक विचारों से लैस होना, जो बेहद कठिन कार्य है।

थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार एक बार में नहीं, 1000 बार विफल होने के बाद किया था। इतनी बार विफल होने से एक साधारण व्यक्ति बिखर जाता है या नकारात्मक्ता में डूब जाता है, मगर एडिसन सदैव सकारात्मक विचारों से लैस रहे। दरअसल विपरीत परिस्थितियां हमारा अवलोकन करने के उद्देश्य से आती हैं। हमारी आंतरिक शक्ति को परखने का कार्य करती हैं, मगर इंसान यह भूल जाता है कि जैसे कोयला धरती की गहराई में ताप व दबाव सहकर ही हीरा बनता है, चंदन घिसने के बाद ही खुशबू देता है, उसी प्रकार एक इंसान साधारण से असाधारण तभी बनता है, जब वह विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मक विचार रखते हुए उसका प्रतिबद्धता के साथ सामना करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। आजकल आत्महत्या की ज्यादा खबरें आ रही हैं। लोग आत्महत्या करके अपने इस अमूल्य जीवन का अंत इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि वे आंतरिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि नकारात्मक विचार उन पर इस कदर हावी हैं कि वे अपनी सूझ-बूझ खो बैठे हैं। वे जीवनधारा के विपरीत बह रहे हैं। जीवन को शांत और सहज बनाने के लिए सकारात्मक विचारों का आना अत्यंत आवश्यक है। इंसान परमात्मा के प्रति आस्था और श्रद्धा रखकर खुद के अंदर सकारात्मक विचारों को उजागर कर सकता है और जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाए रख सकता है।

सौरभ पाठक

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

सिर्फ उच्च डिग्री ही काफी नहीं

बेहतर शिक्षकों के चयन की चुनौती शीर्षक से लिखे अपने लेख में निरंजन कुमार ने देश में शिक्षकों की भर्तियों में सुधार के कुछ उपाय सुझाए हैं। हमारे देश में भी शिक्षकों की भर्ती काफी जटिल प्रक्रिया से की जाती है, शैक्षणिक योग्यता के आधार भी की जाती है, लेकिन जरूरी नहीं कि उच्च योग्यता वाला ही बेहतर शिक्षक सिद्ध हो। बेहतर शिक्षकों का चयन तभी संभव है जब उच्च शिक्षा के साथ नैतिकता, इंसानियत का सबक भी इनको पढ़ाया जाए और उसका भी इम्तिहान लिया जाए। जबसे शिक्षा का बाजारीकरण हुआ है तबसे शिक्षामंदिरों की दुर्दशा हो गई है? गुरु और शिष्य का संबंध ग्राहक और दुकानदार का हो गया है। इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि आधुनिक दौर में शिक्षा भी एक व्यापार बन गई है, यानी कि कुछ लोग अपने ज्ञान को बांटने के लिए बहुत मोटी रकम लेते हैं। जिस कारण गरीब बच्चों को बहुत मुश्किल होती है। अंत में यह कहना भी उचित होगा कि शिक्षा संस्थानों का यह भी मकसद होना चाहिए कि वे विद्यार्थियों को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या अन्य विशेषज्ञ बनाने के साथ-साथ आदर्श और मर्यादित भी बनाएं।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाक को जवाब

देश वीर जवान अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सीमा पर शहीद हो रहे हैं। ये किसी युद्ध में नहीं, बल्कि पाकिस्तान की हरकतों की वजह से शहीद हो रहे हैं। हमें पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना होगा, तभी शहीद जवानों को सच्ची श्रद्धांजली होगी और वह ऐसी हरकत करने से बाज आएगा।

युधिष्ठिर लाल कक्कड़, गुरुग्राम

मन की बात

प्रधानमंत्री ने मन की बात की श्रृंखला में मात्र 30 मिनट के संबोधन में गागर में सागर भर दिया। गुरु नानकदेव व संत कबीर से लेकर स्वर्गीय डा. श्यामा प्रसाद मुकर्जी तक को याद कर उनके कार्यों को याद किया। जालियांवाला बाग का भी उल्लेख किया और इसके साथ ही सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी।

dharmendranath.rastogi@gmail.com

शिक्षक का सम्मान

एक शिक्षक अपने समाज की नींव भरने में बहुत बड़ा योगदान देता है। वह अपने विनम्र स्वभाव के कारण विद्यार्थियों के बीच एक अलग जगह बना लेता है। शिक्षक का कहा कोई भी विद्यार्थी अनसुना कर ही नहीं पाता। कुछ गुरु-शिष्य संबंध तो आजीवन बने रहते हैं। कुछ ऐसा ही चेन्नई के वेलिग्राम गवर्नमेंट स्कूल के अंग्रेजी शिक्षक के बारे में पढ़ने को मिला। अध्यापक भगवान के तबादला होने पर उनके विद्यार्थियों ने रो-रो कर उन्हें अपने विद्यालय से जाने से रोकने की कोशिश की। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों से मिला प्रेम व सम्मान मिलने वाले अन्य सभी सम्मान से सर्वोपरि है।

दीपा डिंगोलिया, दिल्ली

महिला हक की लड़ाई

महिलाएं पहले घर आंगन में ही काम करती थीं, अब महिलाएं हर रुढ़िवादी परंपरा को तोड़ कर आगे बढ़ रही हैं। वह समाज में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण सऊदी अरब की महिलाएं हैं। जहां पर महिलाओं पर अभी भी सदियों पुराने कड़े नियम लागू हैं। वहां की महिलाएं भी अब अपने हक की लड़ाई लड़ कर आगे बढ़ी हैं। सऊदी अरब में 24 जून 2018 को पहली बार महिलाओं को वाहन चलाने का अधिकार मिला है, सरकार ने उनके वाहन चलाने पर प्रतिबंध को हटा लिया है।

shivanityagi0027@gmail.com

जल संचय के उपाय जरूरी

ब्रह्मांड में पृथ्वी ही हरी-नीली अभिनव रंगों से आभायुक्त एकमात्र ग्रह है, जिस पर सांसों के स्पंदन से युक्त चलते फिरते जीव, रंग-बिरंगी तितलियों, चिड़ियों, फूलों व फलों से लदे हरे-भरे पेड़-पौधे, लताएं, रिमझिम बरसात, जंगलों और बर्फ से ढके पहाड़, हरे विशालकाय घास के मखमली अंतहीन सपाट मैदान, उसमें अठखेलियां करते विभिन्नताओं से परिपूर्ण तरह-तरह के जीव-जन्तु आदि हैं। इस अनुपम धरती की ये समस्त जैव और वानस्पतिक संपदा के मूल में इस अनोखे ग्रह पर पानी और हवा की उपस्थिति है। अगर ये दोनों चीजें नहीं रहतीं, तो यह ग्रह (पृथ्वी) भी इस अनन्त ब्रह्मांड के अरबों-खरबों अन्य निर्जीव ग्रहों की तरह ही जीवन के स्पंदन के बिना एकदम वीरान होती। पृथ्वी का दो तिहाई भाग जल और एक तिहाई भाग थल है। पर्यावरण विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में कुल उपलब्ध पानी का लगभग 70 प्रतिशत पानी प्रदूषित है। उत्तर की डल झील से लेकर दक्षिण की पेरियार झील तक पूर्व में दामोदर व हुगली नदी से लेकर पश्चिम में ठाणा उपनदी तक पानी के प्रदूषण की स्थिति एक सी ही भयानक है। गंगा जैसी सदानीरा नदियां भी आज प्रदूषित हो चुकी हैं। वनों के अंधाधुंध कटाई, प्रकृति का दोहन और भूमि व जल संरक्षण के प्रति शासन की लापरवाही के कारण ही भारतीय प्रायद्वीप के विश्व प्रसिद्ध चेरापूंजी, जो दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश के लिए प्रसिद्ध है, वहां सालभर में औसतन 9150 मिली मीटर बारिश होती है, फिर भी जल संकट से जूझ रहा है। भारत में भूगर्भीय जल का अत्यधिक दोहन होने के कारण धरती की कोख सूख रही है। जहां मीठे पानी का प्रतिशत कम हुआ है, वहीं जल की लवणीयता बढ़ने से भी समस्या विकट हुई है। यदि हमें जीवन को बचाना है तो जल संरक्षण और संचय के उपाय करने ही होंगे।

निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद

ट्वीट-ट्वीट

यदि जीएसटी 'ईमानदारी की जीत' और 'ईमानदारी का उत्सव' है तो भाजपा ने इसका विरोध क्यों किया और क्यों इसे पांच वर्षों तक रोका?

पी चिदंबरम@PChidambaram_IN

भाजपा ने इसका विरोध इसलिए किया, क्योंकि तब सत्तारूढ़ संप्रग सरकार ने राज्यों को वैसी उचित पेशकश नहीं की थी जैसी भाजपा शासन में राज्यों को मिली